

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4068
बुधवार, दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

4068. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के तहत क्या प्रगति हुई है;
- (ख) एनजीएचएम के तहत अब तक कितनी निधि आबंटित और उपयोग की गई; और
- (ग) शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हरित हाइड्रोजन का अपेक्षित योगदान कितना है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) का कार्यान्वयन कर रही है। मिशन को जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19,744 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय के साथ स्वीकृति दी गई थी।

एनजीएचएम के तहत, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करना है, जिससे प्रतिवर्ष CO₂ उत्सर्जन में लगभग 50 एमएमटी की कमी आएगी।

एनजीएचएम के तहत हुई प्रगति निम्नानुसार है:

- i. साइट (ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप) कार्यक्रम के तहत:
 - क. 15 कंपनियों को 3000 मेगावाट प्रति वर्ष इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता आबंटित की गई है।
 - ख. 16 कंपनियों को 7,56,100 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता आबंटित की गई।

- ग. पूरे भारत में 11 उर्वरक इकाइयों को ग्रीन अमोनिया (ग्रीन हाइड्रोजन का डिरेक्टिव) के 6,70,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) के उत्पादन और आपूर्ति के लिए ग्रीन अमोनिया बिक्री और खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- घ. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) की रिफाइनरियों को आपूर्ति के लिए 30,000 टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और आपूर्ति क्षमता प्रदान की गई है।
- ii. इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए चार पायलट परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
 - iii. वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी को बंदरगाह पर ग्रीन मेथनॉल के लिए बंकरिंग और ईंधन पुनर्भरण सुविधा के विकास के लिए एक परियोजना आबंटित की गई है।
 - iv. भारतीय नौवहन निगम को ग्रीन मेथनॉल अनुकूल दोहरे ईंधन वाले जहाज का अधिग्रहण करने के लिए एक परियोजना आबंटित की गई है।
 - v. पूरे भारत में 21 विभिन्न मार्गों पर 16 हाइड्रोजन ईंधन पुनर्भरण स्टेशनों (एचआरएस) के साथ 70 हाइड्रोजन ईंधन वाले वाहनों के प्रचालन के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
 - vi. चार परियोजनाओं को हाइड्रोजन वैली अर्थात् जोधपुर हाइड्रोजन वैली, ओडिशा हाइड्रोजन वैली, पुणे हाइड्रोजन वैली और केरल हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर (एचवीआईसी) के रूप में आबंटित किया गया है।
 - vii. परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए सात परियोजनाएं (7) स्वीकृत की गई हैं।
 - viii. एनजीएचएम की अनुसंधान और विकास (अनुसंधान एवं विकास) योजना के हिस्से के रूप में सत्ताईस (27 परियोजनाएं) स्वीकृत की गई हैं।
 - ix. अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए चार (4) परियोजनाएं आबंटित की गई हैं।

दिनांक 6 अगस्त 2026 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 292.45 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।
